less orders given to the factory. Although, the factory has enough buildings, land, technical knowhow, etc. to accommodate and to employ double the number of workers, if the workload is increased. I would ask the Minister to secure large number of orders such as stitching of uniforms for para-military Forces, i.e., Border Security Force, Central Reserve Police, Indo-Tibetan Border Police, Industrial Security Force, Railway Protection Force and Civil and Armed Police of Area State. There are many items of clothing uniforms which are required by the Armed Forces but are being manufactured by private companies. All these items should be diverted to the Ordnance Clothing Factory, Shahjahanpur so that the employment potential of this factory is increased by hundred per cent which in turn will reduce unemployment and also supply better quality goods to the Armed Forces and other Government organisations.

(iii) STEPS TO ABOLISH DEVDASI SYSTEM IN KARNATAKA.

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी ही पीड़ा एवं लज्जा का विषय है कि 33 साल की आजादी के बाद भी आज देश के एक भाग—कर्नाटक—में देवदासी प्रथा प्रचलित है। दकियानूसी विचारों एवं अंध विश्वासों पर आधारित, भोग विलास में लिप्त स्वेण पुजारियों द्वारा धर्म की आड़ में अनभिज्ञ एवं निरीह अबलाओं के साथ सदियों पुराना चला आ रहा यह कुचक्र आज स्वतन्त्र भारत के मस्तिष्क पर कलंक का टीका मात्र बन कर रह गया है। विदित हुआ है कि आज भी प्रतिवर्ष लगभग पांच हजार देवदासियां बनाई जा रही हैं। उनमें अधिकांश बम्बई, पुणे, कोल्हापुर आदि नगरों में अपनी अस्मत बेचने को बाध्य हो रही हैं। यह नारी उत्पीड़न की पराकाष्ठा है। यह कितना अमानवीय है कि 5, 6 वर्ष की अबोध बालिकाएं देवदासी बना दी जाती हैं और वे जीवन पर्यन्त कठोर यातनाएं सहती रहती हैं।

क्षोभ की बात है कि इस घृणित प्रथा के उन्मूलन के लिए जो भी उपाय अपनाये गए वे पूर्णरूपेण प्रभावहीन हैं। 1907 में मैसूर के तत्कालीन महाराजा ने इस प्रथा पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। तत्पश्चात् ब्रिटिश शासन में 1934 में देवदासी संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। परन्तु निष्ठा के अभाव में इनका कार्यान्वयन विशेष लाभकारी सिद्ध नहीं हुआ।

मैं माननीय समाज कल्याण मंत्री जी से सविनय आग्रह करूंगा कि जो भी उपाय आवश्यक हों, तत्काल कठोरता से अपनाये जाएं जिससे इस लज्जाजनक प्रथा का अविलम्ब उन्मूलन हो सके। साथ ही वर्तमान देवदासियों के पुनर्वास एवं जीविकोपार्जन के लिए प्रभावकारी एवं व्यावहारिक कार्यक्रम चलाये जायें जिससे उन्हें अपनी दुखियारी जिन्दगी में कुछ राहत मिल सके।

(iv) REPORTED CLOSURE OF THE JAWAHAR LAL NEHRU UNIVERSITY'S CENTRE OF STUDIES IN SCIENCE POLICY.

SHRI K. A RAJAN (Trichur): Sir, it is reliably learnt that the J. N. U. authorities are toying with the idea of closing down the University's centre of studies in Science policy. This will jeopardise the careers of students.

The Ramanna Committee was appointed to formulate a workable programme for study of science policy in the University, not to kill what is existing.

Even prior to the Ramanna Committee Report, the Centre had virtually been suspnded since last March.